



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 14, 2005/आश्विन 22, 1927

No. 141]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2005/ASVINA 22, 1927

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 7 अक्टूबर, 2005

सं. टीएएमपी/80/2000-सीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा कोलकाता पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान और वेतन, दिहाड़ी और पेंशन की बकाया राशियों की मद में देयताओं को पूरा करने हेतु विशेष दर की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/80/2000-सीपीटी

आदेश

(अक्टूबर, 2005 के छठे दिन पारित)

यह प्रकरण केओपीटी के वर्तमान दरमान केओपीटी के प्रचलित दरमान और पत्तन उपयोगकर्ताओं द्वारा 30 सितम्बर, 2005 के बाद देय विभिन्न प्रभारों पर निर्धारित की गई 10% की विशेष दर की वैधता बढ़ाने से संबंधित है।

2. जैसाकि पहले बताया जा चुका है, केओपीटी के प्रचलित दरमान और 10% की विशेष दर की वैधता 30 सितम्बर, 2005 को समाप्त हो गई है। केओपीटी ने अपने दरमान के संशोधन के लिए 22 जुलाई, 2005 को सामान्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव में 31 मार्च, 2007 तक लागू पत्तन प्रभारों पर 10% की विशेष दर का विस्तार भी शामिल है। कथित सामान्य संशोधन प्रस्ताव को विचारार्थ ले लिया गया है। केओपीटी द्वारा दाखिल किए गए सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर अपनाई गई सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए कार्रवाई की जा रही है और अंतिम विचार-विमर्श के लिए प्रकरण को परिपक्व होने में कुछ और समय लगेगा। अतएव, यह प्रकरण, केओपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता को 30 सितम्बर, 2005 से आगे विस्तार प्रदान करने का इरादा रखता है।

3.1. केओपीटी ने इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सामान्य संशोधन प्रस्ताव के साथ 31 दिसम्बर, 2000 तक जारी किए गए विभिन्न सरकारी आदेशों से प्रोद्भूत वेतन, दिहाड़ी और सेवा निवृत्ति लाभों की बकाया राशि की मद में केओपीटी की देयताओं के संबंध में एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। वेतन, दिहाड़ी, पेंशन लाभ की बकाया राशियों और इन राशियों के भुगतान के लिए बैंक से लिए गए ऋण पर 31 मार्च, 2001 तक जमा हुए देय ब्याज की मद में कुल देनदारी का संशोधित अनुमान 227.89 करोड़ रुपये बताया जाता है। इस संबंध में पत्तन द्वारा प्रस्तुत लेखा-परीक्षित स्थिति से यह पाया गया है कि पत्तन ने 30 जून, 2005 तक अपनी 250.74 करोड़ रुपये तक की देनदारियाँ भुगतान कर दी हैं और कुल देनदारियों और अर्जित राजस्व तथा कथित प्रयोजन के लिए 10% की विशेष दर से अर्जित किए जाने वाले राजस्व के बीच 64.97 करोड़ रुपये की कमी दिखाई देती है। यह ध्यान देने योग्य है कि 10% की विशेष दर से जून, 2005 तक उत्पन्न हुआ राजस्व 212.92 करोड़ रुपये बताया गया है। इसने आगे बताया है कि इस विशेष दर से 31 मार्च, 2006 तक 56.27 करोड़ रुपये की उगाही होने का अनुमान है। विशेष दर से उद्भूत राजस्व और

विशेष दर से उत्पन्न होने वाले राजस्व बकाया देनदारियों की मद में प्रोद्भूत कुल संशोधित देनदारियों और पहले ही भुगतान कर दी गई देनदारियों की मात्रा को लेखा-परीक्षा द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है।

3.2. चूंकि केओपीटी ने अपना सामान्य संशोधन प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। विशेष दर की मात्रा और अवधि का मूल्यांकन, अपनाए जाने वाले राजस्व मॉडल के संदर्भ से किया जा सकता है। उस समय तक के लिए, केओपीटी द्वारा बताई गई बकाया देनदारियों की मात्रा पर ध्यान देते हुए यह प्राधिकरण लागू प्रभावों पर 10% की विशेष दर को 30 सितम्बर, 2005 से, पत्तन के सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले आदेश की अधिसूचना के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक की अवधि तक विस्तार प्रदान करने का इरादा रखता है।

3.3. परिणामस्वरूप, और ऊपर वर्णित कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण केओपीटी के प्रचलित दरमान और 10% की विशेष दर को, केओपीटी द्वारा दाखिल सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक विस्तार प्रदान करता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/05-असाधारण]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 7th October, 2005

No. TAMP/80/2000-CPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (36 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Kolkata Port Trust and the special rate fixed to meet the liability on account of arrears of salary, wages and pension as in the order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/80/2000-CPT

ORDER

(Passed on this 6th day of October, 2005)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of KOPT and the 10% special rate fixed of the respective charges payable by the port users beyond 30th September, 2005.

2. As stated earlier, the validity of the existing Scale of Rates of KOPT as well as the 10% special rate expire on 30th September, 2005. The KOPT has filed a general revision proposal for revision of its Scale of Rates vide its proposal dated 22nd July, 2005. The proposal includes extension of special rate of 10% on applicable port charges till 31st March, 2007. The said general revision proposal has been taken on consultation. The general revision proposal filed by the KOPT is being processed following the usual consultation process adopted and it will take some more time for the case to mature for final consideration. This Authority is, therefore, inclined to extend the validity of the existing Scale of Rates of KOPT beyond 30th September, 2005.

3.1. The KOPT has furnished a certificate of an independent auditor relating to the liability of the KOPT on account of arrears of salary, wages and retirement benefits arising out of various Government Orders issued till 31st December, 2000 along with its general revision proposal filed before this Authority. The revised estimates of the total liability on account of arrears of salaries, wages, pension benefits and interest payable on bank loans obtained for releasing the arrears accrued upto 31st March, 2001 is reported at Rs. 277.89 Crores. From the audited position furnished by the port in this regard, it is found that the port has discharged its liability to the extent of Rs. 250.74 Crores upto 30th June, 2005 and a shortfall of Rs. 64.97 Crores between the total liability and the revenue generated and to be generated from 10% special rate for the said purposes is seen. It is noteworthy that the revenue generated from 10% special rate upto June 2005 is reported to be Rs. 212.92 Crores. It has further stated that Rs. 56.27 Crores is estimated to be realized out of the special rate up to 31st March, 2006. The revenue generated and to be generated from the special rate, the total revised liabilities accrued on account of arrears liabilities and the quantum of arrears liabilities already discharged have been certified by the Audit.

3.2 Since the KOPT has filed its general revision proposal the quantum and duration for special rate can be further assessed with reference to the revenue model to be considered. Till such time, considering the quantum of arrear liabilities reported by KOPT, this Authority is inclined to extend the 10% special rate on the applicable charges for a period beyond 30th September, 2005 till the effective date of implementation of notification of the Order to be passed on the port's general revision proposal.

3.3 In the result, and for the reasons given above and based on the collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing Scale of Rates of KOPT and the 10% special rate till the effective date of implementation of the Order to be passed on the general revision proposal filed by the KOPT.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADV/III/IV/143/05-Exty.]